कुशल भारत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक लाख से अधिक निर्माण मजदूरों को कौशल, कौशल उन्नयन करने के लिए निपुण परियोजना प्रारम्भ किया

नई दिल्ली, 20 जून, 2022: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत नोडल एजेंसी ने आज निपुण अर्थात निर्माण मजदूरों के कौशल संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पहल परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य एक लाख से अधिक निर्माण मजदूरों को नए कौशल और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना और उन्हें विदेशों में अवसर प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयन को तीन अध्यायों में विभाजित किया गया है - निर्माण स्थलों पर पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से प्रशिक्षण, नलसाजी और अवसंरचना एसएससी द्वारा नवकौशल के माध्यम से प्रशिक्षण तथा उद्योगों/बिल्डरों/ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नियोजन।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ सह-ब्रांडेड आरपीएल प्रमाणन के तहत उद्योग संघों के माध्यम से 80,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन-साइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि 14,000 उम्मीदवारों को नालसाजी और अवसंरचना क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) के माध्यम से नए कौशल प्राप्त होंगे। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित हैं और प्रत्यायित तथा संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रदान किए जाएंगे। एनएसडीसी का लक्ष्य सऊदी अरब साम्राज्य, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य जीसीसी देशों जैसे विदेशों में कम से कम 12,000 लोगों को नियोजन प्रदान करना है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) की अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम के तहत, एमओएचयूए के तत्वावधान में परियोजना निपुन का संचालन किया जाएगा। यह संबंधित मंत्रालयों के साथ अभिकेंद्रण की सुविधा और समर्थन भी देगा। इस बीच, एनएसडीसी प्रशिक्षण, अनुवीक्षण और उम्मीदवार ट्रैकिंग के समग्र निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। यह प्रशिक्षुओं को कौशल बीमा (3 साल का दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये के कवरेज के साथ), डिजिटल कौशल जैसे कैश-लेस लेनदेन और भीम ऐप, उद्यमशीलता के बारे में अभिविन्यास, तथा ईपीएफ और बीओसीडब्ल्यू सुविधाएं प्रदान करेगा। परियोजना की देखरेख और अनुवीक्षण के लिए अपर सचिव-सह-मिशन निदेशक, डीएवाई-एनयूएलएम की अध्यक्षता में एनएसडीसी और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दोनों के सदस्यों के साथ एक परियोजना समिति का गठन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, **आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस पुरी** ने कहा, “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

(एनयूएलएम) के परिवर्तनकारी प्रभाव ने निश्चित रूप से शहरी निवासियों, विशेषकर युवाओं को कौशल उनयन और रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी गरीब परिवारों की भेद्यता को कम किया है। शहरी श्रमिकों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित और समर्थित किया गया है। यह पहल निर्माण मजदूरों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर और उनके कौशल सेट में विविधता लाने के द्वारा निर्माण उद्योग में भविष्य के रुझानों को अपनाने के दौरान अधिक दक्ष और कुशल बनाने में सक्षम बनाएगी।"

मंत्री ने यह भी घोषणा किया है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आगामी कुछ दिनों में खोले जाएंगे।

एनएसडीसी और एमओएचयूए के बीच साझेदारी की सराहना करते हुए, **एमएसडीई के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल** ने कहा, "निर्माण उद्योग 2022 तक सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की ओर अग्रसर है, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि एनएसडीसी और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की यह अनूठी परियोजना, हमारे सभी हितधारकों के समर्थन के साथ, निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी के अवसर, बेहतर लाभ और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के साथ प्रदान करेगी, जिससे वे न केवल एक आत्मानिर्भर भारत के पथ प्रदर्शक बनेंगे, बल्कि भारत को शेष विश्व के लिए एक कौशल केंद्र में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"

निर्माण उद्योग 2022 तक सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की ओर अग्रसर है और अगले 10 वर्षों में 45 मिलियन अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) उद्योग भागीदारों के रूप में निपुण परियोजना में शामिल हुए हैं और एसएससी के सहयोग से निर्माण क्षेत्र में आकांक्षात्मक मूल्य की प्रशिक्षण जॉब रोलों की पहचान करेंगे।

<u>राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में</u>

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), एक नोडल कौशल विकास एजेंसी है जो भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत काम कर रही है, एक अनूठी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) है जिसका उद्देश्य भारत में एक बड़े गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण इको सिस्टम और उद्यम के निर्माण को उत्प्रेरित करना है। 2010 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएसडीसी ने देश के 600 से अधिक जिलों में 600 से अधिक प्रशिक्षण भागीदारों और 10,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। एनएसडीसी ने 37 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) की स्थापना की है और सरकार की प्रमुख कौशल विकास स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) को कार्यान्वित करता है। एनएसडीसी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को भी निधि प्रदान करता है। संगठन रियायती ऋण, अन्य नवीन वित्तीय उत्पादों और रणनीतिक साझेदारी की पेशकश करके कौशल विकास में निजी क्षेत्र की क्षमता निर्माण को सक्षम बनाता है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के बारे में

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय देश में आवास और शहरी मामलों से संबंधित सभी मुद्दों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का सर्वोच्च प्राधिकरण है, जो नीति निर्माण कार्यक्रम, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारें और नोडल प्राधिकरण की कार्यकलापों को प्रायोजित करने और समर्थन करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यक्रमों के समन्वय और अनुवीक्षण का कार्य करता है।